अपनी भाषा

ISSN : 2349-0470
वर्ष : 17, अंक :19, दिसंबर 2017

भाषा विमर्श

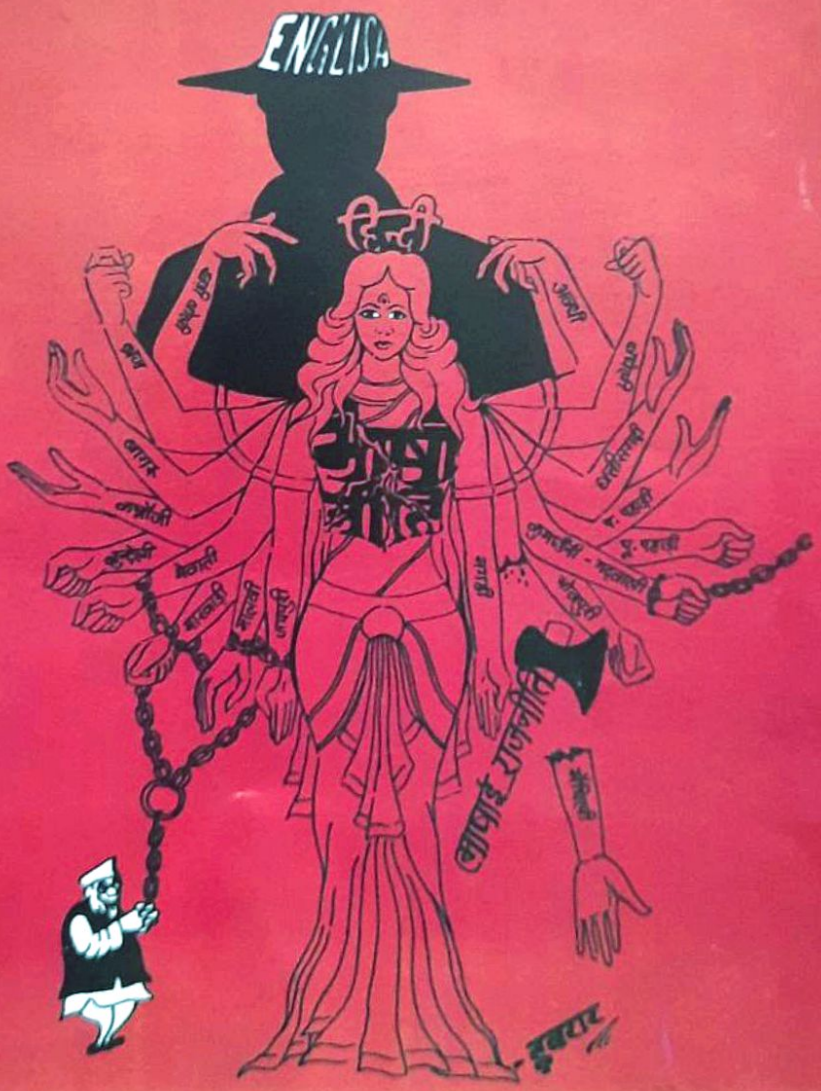

अनुक्रमणिका

महासचिव की वार्षिक रपट-2016-2017		5
अंग्रेजी माध्यम आत्मघाती होगा	गोविन्द सिंह	8
यूपी सरकार चलाएगी 5000 सरकारी अंग्रेजी माध्यम प्राइमरी स्कूल		9
प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम में मिलेगी शिक्षा : दक्षिणी निगम		9
जनता की कायरता और गुलाम मानसिकता तथा शासक वर्ग की शोषणप्रियता और बेईमानी में विश्व के किसी भी देश की भारत से कोई बराबरी नहीं	श्यामरूद्र पाठक	10
हिन्दी गई कहाँ?	प्रो. बी.वै. ललिताम्बा	11
भाषाई पड़ताल का महाउद्यम	डॉ. ऋषिकेश राय	13
हिन्दी का संकट	डॉ. पंकज साहा	16
सांस्कृतिक गुलामी	ग्राम्शी	17
डॉ. वेद प्रताप वैदिक	डॉ.एम.एल गुप्ता आदित्य	18
सरकारी आंकड़ों में सिमटती हिन्दी	विनय कुमार शुक्ल	20
उत्तराखण्ड में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई	डॉ. रचना पाण्डेय	22
गोरखालैंड और भाषा की राजनीति	डॉ. अर्चना द्विवेदी	24
भूमंडलीकरण के दौर में हिन्दी : दशा एवं दिशा	नीरज कुमार चौधरी	25
डायग्लोसिया	लिली साह	27
कर्नाटक में हिन्दी की दशा	टी.जी. प्रभाशंकर 'प्रेमी'	29

उत्तराखण्ड में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई

–डॉ. रचना पाण्डेय*

देशभर में अंग्रेजी को शिक्षण का माध्यम बनाने की एक सनक सी चल पड़ी है। हिन्दी शैक्षणिक संस्थाएँ भी एक-एक कर इस सनक की भेंट चढ़ती जा रही हैं। निजी विद्यालय तो बाज़ार की दौड़ में अपने आप को बनाए रखने के लिए तो मजबूर हैं ही, लेकिन अब सरकारी विद्यालय भी इस दौड़ में शामिल होने के लिए आगे बढ़े हैं। इसी दौड़ में उत्तराखण्ड की सरकार भी आ गयी है। शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों और शिक्षकों को लगता है कि सरकारी विद्यालयों की घटती छात्र संख्या का एक बड़ा कारण इनका अंग्रेजी माध्यम में न होना है। घटती छात्र संख्या को रोकने का एकमात्र इलाज इन्हें विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में बदल देना ही दिखाई दे रहा है। अंग्रेजी के प्रति अतिशय मोहग्रस्त मध्यवर्ग इस कदम से आकर्षित होकर विद्यालयों की ओर हो सकता है लौट आए। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के पीछे कई तर्क भी सामने रखे गए हैं। मसलन कम उम्र से ही अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करने से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की भावना बलवती होगी, हिन्दी माध्यम से पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आगे की शिक्षा में तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, आज के परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजी का अर्थ शक्ति है आदि।

उपर्युक्त दलीलों का हवाला देते हुए ही उत्तराखण्ड की सरकार ने लगभग 18,000 सरकारी विद्यालयों के 2018-19 के शैक्षणिक सत्र में पहली कक्षा से शिक्षा का माध्यम हिन्दी के बदले अंग्रेजी को बनाने का ऐलान किया है। राज्य के शिक्षामंत्री श्री अरविन्द पाण्डेय के अनुसार इस योजना को चरणों में पूरा किया जाएगा। योजना को कार्यान्वित करने के लिए अंग्रेजी में किताबों को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी। शुरुआत में बच्चों को छोटे-छोटे वाक्य सिखाए जाएँगे ताकि आसानी से वे बाद के जटिल वाक्यों को समझ सकने में सक्षम हो सकेंगे। वाक्यों की सूची State Council of Educational Research & Training (SCERT) द्वारा तैयार किया जा रहा है। उप शिक्षामंत्री श्री पंकज कुमार ने शिक्षकों से चालू शैक्षिक सत्र में कक्षा में छोटे-छोटे वाक्यों को लटकाने की सलाह दी है। (my apologies, have a good weekend, I am obliged, what a nice day) जैसे शब्दों और वाक्यों की संख्या 75 निर्धारित की गई है।

उत्तराखण्ड की सरकार ने हिन्दी को पदाक्रान्त करके अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना तय किया है परंतु यह बात ध्यान में नहीं रखा गया कि मातृभाषा में शिक्षा नहीं होने से विद्यार्थियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह सिद्ध हो चुका है कि मातृभाषा में शिक्षा बच्चों के उन्मुक्त विकास में ज्यादा कारगर होती है। एक तो अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, वह पड़ी हुई नहीं मिल जाती। इसे रटाया जाता है जिससे वह आत्मा में प्रवेश नहीं कर पाती। कोई भाषा सीखना अच्छी बात है, वह हमें एक नए संसार में प्रवेश कराती है। लेकिन मातृभाषा की उपेक्षा कर शिक्षा के माध्यम से उसे हटाकर जिस तरह के भाषा संस्कार डाले जा रहे हैं वह खतरनाक है। अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करना बच्चे का अधिकार है उस पर दूसरी भाषा का बोझ लाद देना उसके स्वाभाविक विकास में बाधा पहुँचाना है। अन्य माध्यम से पढ़ने वाले को एक अतिरिक्त भाषा का बोझ उठाना पड़ता है। पहले बच्चे एक पराई भाषा को पढ़ते हैं फिर उसका अनुवाद कर उसे समझते हैं और दुबारा अनुवाद कर उसे लिखते हैं। परिणामतः वह दोनों भाषाओं के साथ न्याय नहीं कर पाते और उनकी पठन क्षमता क्रमशः कम होती जाती है। यह बात भी विचारणीय है कि बच्चे क्या केवल पाठ्यक्रम से भाषा की ही पढ़ाई करते रह जाएँगे या अन्य विषयों पर भी केन्द्रित होंगे। यदि हम यह सोचते हैं कि विकास का मॉडल अंग्रेजी भाषा पर ही खड़ा होगा तो यह हमारा भ्रम ही है। स्वीडन में स्वीडीश, फिन्लेन्ड में फिनीश, फ्रान्स में फ्रेन्च, ईटली में इटालवी, ग्रीस में ग्रीक, जर्मनी में जर्मन, ब्रिटेन में अंग्रेजी, चीन में चाईनीज़ और जापान में जापानी भाषाएँ शिक्षा का माध्यम हैं। तकनीकी दृष्टि से ये सारे देश विश्व में आगे हैं।

हम झूठ, फरेब, पाखंड में अपनी ही वस्तुएँ नष्ट होते देख रहे हैं। सरकार की कथनी और करनी में इतनी चौड़ी खाई इससे पहले कभी नहीं रही। अंग्रेज जो कार्य नहीं कर पाए वही कार्य उत्तराखण्ड की सरकार ने कर दिखाया। सच्चाई तो यह है कि सरकारी विद्यालयों की आधारिक संरचना ध्वंस हो चुकी है। इसे सुधारने के लालच में निजीकरण किया जा रहा है। शिक्षा में राजनीतिक लाभ को ध्यान में रखकर बदलाव करने के स्थान पर शैक्षणिक दृष्टि से आवश्यक बदलाव लाना आज की परिस्थिति में सराहनीय कदम होगा। किसी दूसरी भाषा को

---

* सहायक प्रोफेसर, हिंदी विभाग, श्री शिक्षायतन कॉलेज, कोलकाता